

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-17/2014

राजकुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 12.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अभिभाषक

प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड—तृतीय के पद पर पंचायती राज विभाग में नियुक्ति आदेश दिनांक 11.08.1981 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी ने पदभार दिनांक 12.08.1981 को ग्रहण किया। अपीलार्थी को 10 एवं 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक 12.08.1981 मानते हुए दिया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर दिनांक 12.08.2008 से दिया जाना चाहिए था परंतु प्रत्यर्था विभाग द्वारा वह लाभ नहीं दिया गया, जिसका आधार यह बताया गया कि अपीलार्थी की नियमित सेवा दिनांक 09.08.1987 से मानी गई है। अपीलार्थी ने तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक 12.08.1981 से नहीं दिये जाने पर अपना अभ्यावेदन भी प्रत्यर्था विभाग को प्रस्तुत किया है, परंतु फिर भी अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नहीं दिया गया है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :-

"It is, therefore, most respectfully Prayed that this appeal may kindly be allowed and call for the entire relating to the case and after examining the same, the respondents be directed to grant the benefit of third ACP with effect from 12.8.2008 after counting his service from the date of initial appointment i.e. 12.8.1981 and in

consequence arrears be also granted to the appellant with 9% interest per annum.

Any other appropriate order or direction which this Hon'ble Court deems fit and proper may kindly be passed in favour of the appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थाई रूप से हुई थी। अपीलार्थी को स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित किया गया था और स्क्रीनिंग की दिनांक से ही अपीलार्थी को सेवा में नियमित माना गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।
3. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जो आदेश दिनांक 11.08.1981 के द्वारा हुई थी वह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी थी, जो तथ्य अपीलार्थी स्वयं भी स्वीकार करता है। अपीलार्थी को बाद में नियमित किया गया और स्क्रीनिंग की दिनांक से अपीलार्थी को नियमित माना गया। अपीलार्थी को तृतीय चयतिन वेतनमान का लाभ नियमितिकरण की दिनांक से ही प्रत्यर्थी विभाग ने प्रदान किया है।
5. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
- (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
- (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
- (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
- (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित किये जाने के पश्चात ही सेवाएं चयनित वेतनमान के लिए गिनी जा सकती है। अपीलार्थी को उससे पूर्व की सेवा तदर्थ आधार पर दी गई है। अतः अपीलार्थी की जो सेवाएं दिनांक 09.08.1987 से नियमित मानी गयी है, उसी दिनांक से अपीलार्थी चयनित वेतनमान एवं अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। उससे पूर्व की सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लिये नहीं जुडवा सकता है।
7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)